मई 2025

ABT
अपना भारत टाइम्स

www.abtnews.in

धर्म या जाति

अन्दर के पन्नों में...

8 यूपी में "चिराग"

7 योगी का 'ब्रह्मास्त्र'

11 कुर्सी पर जमे कर्मी

9 पूर्वांचल बना ख़ास

विषय सूची

03 रोजगार

06 ऑपरेशन सिन्दूर

07 योगी का 'ब्रह्मास्त्र'

08 यूपी में "चिराग"

08 जाति जनगणना

09 पूर्वांचल बना ख़ास

10 यूपी की "ऊर्जा"

10 श्रमिक सराय

11 यूपी के स्कूल

12 व्यक्ति विशेष

रणनीति

पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछ कर उन्हें गोली मार दी. एक ऐसा नरसंहार जिसने देश को आक्रोश से भर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती थी. उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब बहुत हो गया इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेकेंगें, चाहे सीमा ही क्यों लाघनी पड़े, आतंकी घटनाओं में जितनी महिलाओं का सिन्दूर उजड़ा है, उन सबका बदला लिया जायेगा और तभी "ऑपरेशन सिदूर" को लांच कर दिया. इस दौरान अमेरिका जैसे देशों का दवाब भी पीएम मोदी को पीछे ना कर सका, वो ऑपरेशन सिन्दूर की जानकारी लेते रहे हैं और भारतीय सेना ने पकिस्तान के अन्दर घुस कर आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ निश्चय ने पकिस्तान को घुटने पर ला दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। इस बात पर जोर देते हुए कि "यह युद्ध का युग नही है, लेकिन यह आतंकवाद का युग भी नही है," विश्व मीडिया ने प्रधानमंत्री की मुखर भाषा, खासकर परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ उनकी चेतावनियों और भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में उनकी घोषणा को प्रमुखता दी। वाशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री के भाषण पर रिपोर्ट दी, जिसमें इस्लामाबाद को दी गई उनकी चेतावनी को रेखांकित किया गया कि भारत ने केवल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी है और यदि भविष्य में देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वह अपनी शर्तों पर जवाब देगा। भाषण पर बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट मुख्य रूप से पीएम मोदी के सख़्त बयान पर केंद्रित थी, जैसे "पानी और खून एक साथ नही बह सकते," और भविष्य में किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया देने की उनकी चेतावनी। द जापान टाइम्स की रिपोर्ट में परमाणु ब्लैकमेल के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को भी रेखांकित किया गया, साथ ही उनके इस बयान को भी रेखांकित किया गया कि पाकिस्तान के साथ भविष्य की बातचीत केवल आतंकवाद और कश्मीर पर केंद्रित होगी। यही नही, पाकिस्तानी प्रसारक समा टीवी के कवरेज में प्रधानमंत्री मोदी की इस चेतावनी पर ध्यान केंद्रित किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को "निलंबित किया गया है, समाप्त नही किया गया है।" इसमें प्रधानमंत्री के इस बयान का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया कि भारत पाकिस्तान के "परमाणु ब्लैकमेल" से नही डरेगा।

ABT अपना भारत टाइम्स

प्रकाशक "अपना भारत टाइम्स" द्वारा सेक्टर 6, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ 226021 से प्रकाशित एवं Vistaprint (www.vistaprint.in) द्वारा मुद्रित.

UDYAM Reg. No.: UDYAM-UP-30-0014389
GST : 09EPBPS0092J1ZK
कुल पृष्ठ : 12

लेखक : अभिनेन्द्र श्रीवास्तव
फ़ोन: 0522 - 3693654
ई-मेल: editor@abtnews.in

आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम)

लखनऊ | रोजगार को लेकर कई सवाल हैं, कही निजीकरण तो कही निजी कंपनियों के द्वारा नियुक्ति पर भी बवाल है, लेकिन अब योगी सरकार ने इसका समाधान निकाल दिया है और संविदा कर्मियों की बड़ी समस्याओं को अब आसानी से दूर किया जा सकेगा। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां बाहर होंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां शुरू करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर न तो कर्मचारियों का शोषण हो पायेगा और न ही कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी रहेगी। सरकार सैलरी भी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगी। साथ ही न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपए होगा, साथ में पीएफ की सुविधा भी। अब इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम) निर्माण होगा। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कामकाज का पहला ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है।

निगम की ओर से 12 मार्च को नियुक्ति और कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे गये हैं। बताया जा रहा है कि आउटसोर्स कंपनियों को बाहर निकालने के कई कारण हैं जैसे आउटसोर्स कंपनियां चलाने वालों में ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के परिवारजन, रिश्तेदार और मित्र बड़ी संख्या में हैं। कुछ एजेंसियां अच्छे से काम तो कर रही है, लेकिन सरकार के सामने ऐसे भी कई उदाहरण है, जब एजेंसियों ने कर्मचारियों को पूरा वेतन नही दिया और कंपनियों ने कर्मचारियों का पीएफ जमा भी नही कराया। ख़बरों के अनुसार पिछले साल 112 और 1090 की आउटसोर्स कर्मचारियों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था। बताया जा रहा है कि सभी विभाग उनके यहां आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव निगम को भेजेंगें। निगम की ओर से उन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। निगम ही संबंधित विभाग की जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों का चयन करेगा। निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिलें। सेवा शर्तों के मुताबिक पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा हो। बताया जा रहा है कि नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। समूह- ख और ग से जुड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू की कराया जायेगा तो वहीँ समूह- ग के कुछ पदों और समूह घ के सभी पदों पर उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि निगम बनने के बाद वर्तमान में आउटसोर्स से काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी नही जाएगी। संबंधित एजेंसी का जब तक टेंडर है, वह उस अवधि तक काम करेगी।

खबर के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी जब भर्ती हो जायेंगें तो वो काम करते रहेंगे। उनसे एक-एक साल का कांट्रैक्ट तो साइन कराया जाएगा लेकिन आसानी से निकाला नही जायेगा, जब तक कर्मचारी की जरूरत रहेगी, वे संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया या फिर ऑफिस में सेवा नियमावली के खिलाफ कोई काम किया, दुराचरण या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिली तो उन्हें हटा दिया जाएगा। वहीँ नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, लिपिक, ड्राइवर, प्लंबर, लिफ्ट मैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। इनके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पशु चिकित्सक सहित समूह- ख के अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। खबर के अनुसार यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का बजट बीते 6 साल में करीब पौने तीन गुना तक बढ़ गया है। 2019-20 में आउटसोर्स कर्मचारियों पर 684.19 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। जबकि 2025-26 में इसके लिए 1796.93 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम)

श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 16 हजार रुपए होगा। उन्होंने बताया कि अक्सर शिकायत रहती है कि एजेंसी उन्हें निर्धारित मानदेय पूरा नहीं देती। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है। इस उत्पीड़न को दूर करने के लिए निगम आउट सोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित जितने भी विभाग आउटसोर्स से कर्मचारी रखते हैं, उनमें पूरे साल इसकी टेंडर प्रक्रिया चलती रहती है। इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। साथ ही एक साल बाद एजेंसी बदलने पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी चली जाती है। कंपनी अपने कर्मचारी तैनात करती है। निगम बनने के बाद सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती निगम ही करेगा।

यूपी के प्रमुख विभागों में खाली पद

विभाग	स्वीकृत पद	भरे पद	खाली पद
औद्योगिक विकास	4471	1142	3335
भूतत्व एवं खनिकर्म	325	65	260
परिवार कल्याण	43085	26195	16890
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	63729	37508	26221
ग्राम्य विकास विभाग	21160	14656	6922
यूपी पुलिस मुख्यालय	428	309	211
जिला पुलिस संवर्ग	343589	255949	88095
यूपी एसटीएफ	863	519	535
भ्रष्टाचार निवारण संगठन	837	505	351
जेल विभाग	12041	7837	4324
कृषि	26108	13618	12490
पीडब्ल्यूजी	51052	36769	14380
नगर विकास	93	31	62
राजस्व	36583	21834	14749
समाज कल्याण	6040	1969	3947
उच्च शिक्षा	2472	957	1515
चिकित्सा शिक्षा	14493	4553	9940
श्रम विभाग	2612	1141	1471
सूचना विभाग	1252	525	727
वन	12338	7030	5308
वित्त	2609	1004	1605
कोषागार निदेशालय	2818	1301	1517

नोट-आंकड़े यूपी सरकार के हैं।

बजट से समझिए, कैसे आउटसोर्स नौकरियों पर फोकस कर रही सरकार

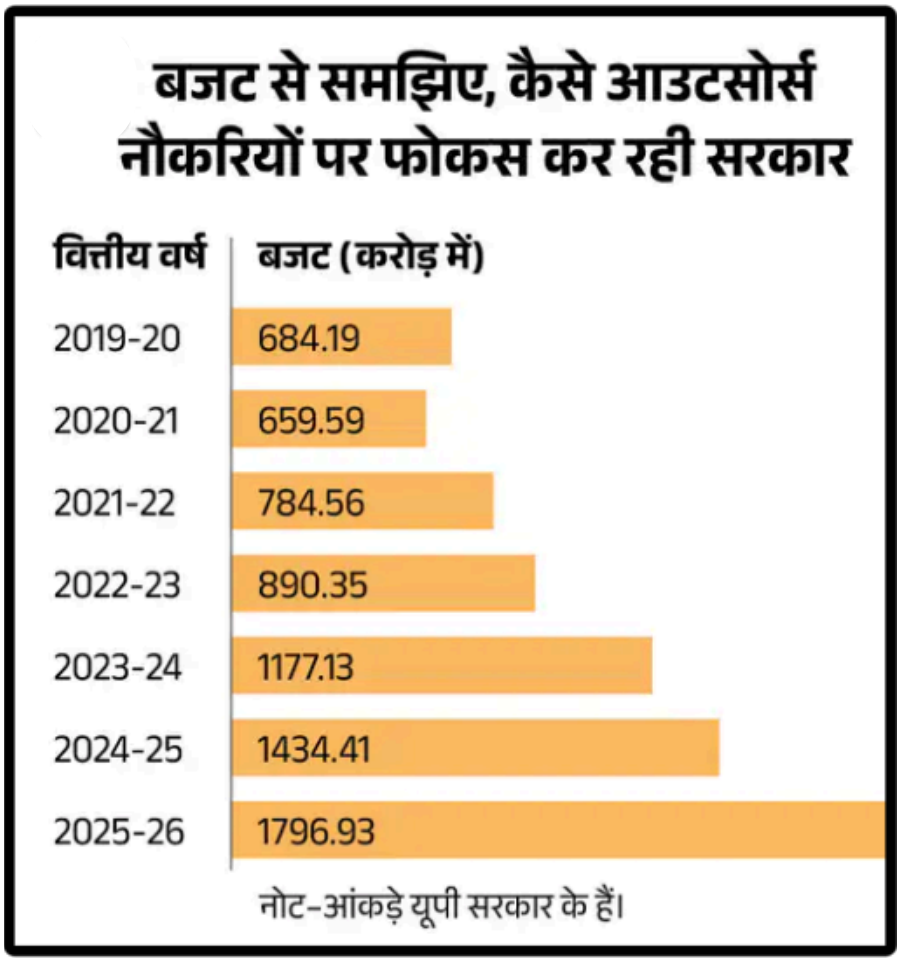

नोट-आंकड़े यूपी सरकार के हैं।

यूपी में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी समूह ग के हैं

नोट-आंकड़े यूपी सरकार के हैं।

प्रमोशन और इंक्रीमेंट का क्या रहेगा, बीमा भी होगा

- संविदा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा में प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। सरकार उनके मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी पर विचार कर समय-समय पर बढ़ाएगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी है।
- उनके मानदेय से पीएफ की कटौती की जाएगी। पीएफ के साथ ही उनका स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा भी होगा।
- अफसर के मुताबिक, ऐसे कई उदाहरण हैं जब आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारियों का सालों का जमा पीएफ की राशि लेकर भाग गई। कर्मचारियों को पता तक नहीं चला कि उनका पीएफ ईपीएफओ में जमा नहीं हुआ।

2017 के पहले चीनी मिल बंद होती थी, अब नई मिल लगाने के प्रस्ताव आ रहे: मुख्यमंत्री

मई के आखिरी सप्ताह में रोजगार को लेकर नयी पहल की शुरुआत देखी गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लैब, आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार लैंड पर जाकर किसानों के साथ कृषि की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्य करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य लैब से लैंड तक जाना है। कृषि वैज्ञानिक लैब के साथ ही लैंड पर भी जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। यह संवाद कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। लैब में जो भी काम हो रहे हैं, वह धरातल पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान का यूपी में शुभारंभ किया। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। इस अभियान के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया। सीएम ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने जो विजन दिया है, कृषि उसकी आधारशिला बनेगी। कृषि के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाया जा सकता है। इस पर कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी-कार्मिक, औद्यानिक फसल, खेती, डेयरी, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को खेती के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस अभिनव पहल के तहत वैज्ञानिक क्लाइमेटिक जोन (भौगोलिक, सामाजिक स्थिति) को देखेंगे और किसानों को अर्ली बीज व लेट वेरायटी का प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है, इसकी भी जानकारी देंगे।

यूपी में कृषि के लिए बहुत स्कोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 वर्ष के अंदर यूपी में डबल इंजन सरकार ने किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के अभियान को अपने हाथों में लिया। यूपी में कृषि के लिए बहुत स्कोप है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10-11 फीसदी हमारे पास है। इसी कृषि योग्य भूमि में यूपी का किसान 22-23 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन करता है। सीएम ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि किसान उनके सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया था। किसान को बीज, एमएसपी का दाम, समय पर खाद्य, खेत के लिए पानी, तकनीक, स्वायल हेल्थ की व्यवस्था नहीं थी। लागत कम, उत्पादक अधिक पर जोर नही था।

पीएम मोदी के शीर्ष एजेंडे में है खेती-किसानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी पीएम मोदी के शीर्ष एजेंडे में है। देश में 11 वर्ष के अंदर खेती-किसानी के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने स्वायल हेल्थ कार्ड का अभियान चलाया। किसानों को पीएम कृषि बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, एमएसपी, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। किसानों को तकनीक से जोड़ने का कार्य हुआ। पिछले 10-11 वर्ष में काफी परिवर्तन हुआ है। 2014-15 में किसान को एक हजार रुपये भी गेहूं का दाम नहीं मिलता था, आज एमएसपी 2425 रुपये है। किसानों ने बाजार में 2800 रुपये में गेहूं बेचा है। यह अन्नदाता किसान के जीवन में आए परिवर्तन का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहाकि यूपी में सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी हुई। 15 लाख किसानों के व्यक्तिगत ट्यूबवेल के कनेक्शन फ्री किए गए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष ढाई हजार करोड़ रुपये जमा करती है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाणसागर परियोजना, अर्जुन सहायक आदि परियोजना के माध्यम से पूरा करते हुए डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए।

जनपदों में जाकर अभियान से जुड़े हैं सरकार के मंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में केवल कृषि विभाग की ही नही, बल्कि जलशक्ति विभाग की भी बड़ी भूमिका है। लखनऊ में कई मंत्री इस अभियान को गति दे रहे हैं तो कुछ मंत्री अनेक जनपदों में जुड़े हैं। इस अभियान से 89 कृषि विज्ञान केंद्र, 826 विकास खंड मुख्यालय, 8137 न्याय पंचायत, किसान कल्याण केंद्र को जोड़ने का कार्य किया गया है। जब इस क्षेत्र से जुड़े लोग अभियान को बढ़ाएंगे तो कृषि के क्षेत्र में नया क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीएम ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हमारी चुनौती है। मॉनसून 15-20 दिन पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन आशंका है कि डेढ़-दो महीने बीच में सूखा रहेगा, फिर बारिश आएगी। उस समय की चुनौती की रणनीति अभी तैयार करनी होगी, फिर बारिश आएगी। यह चेंज उत्पादन पर असर डालेगा। अच्छा बीज पड़ा तो अच्छा उत्पादन होगा, बीज एक महीने लेट होगा तो उत्पादन पर 30 फीसदी का अंतर डालेगा। 8 वर्ष में मिलेट्स, नेचुरल फॉर्मिंग, दलहनी-तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके लिए और भी प्रयास करना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगले चार वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे। इसके लिए नया प्रयास प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। सीएम ने यूपी एग्रीज का भी जिक्र किया। बोले कि पश्चिम के किसानों ने खेती समेत प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, मॉडर्न तकनीक अपनाया, नए बीज उपलब्ध कराए। वे लोग लागत कम करने और उत्पादन बढाने में सफल हुए। मध्य और पूरब के किसान इस दिशा में काफी पीछे थे, इसलिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चार हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने इस वर्ष बढ़ाया है। इससे पूर्वांचल व बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र के 28 जनपदों को आच्छादित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसान अपनी आय को बढ़ा रहा है। 2017 के पहले सुनने को मिलता था कि किसान को पर्ची नहीं मिली तो उसने खेत में आग लगा दी। किसान को वर्षो से गन्ना मूल्य का भुगतान नही होता था। वह मजबूर होकर फसल में आग लगा देता था। किसान का आक्रोश सरकार की स्थिति को बयां कर देता था।

ऑपरेशन सिन्दूर

ख़बर आई कि 22 अप्रैल 2025 को, जम्मू और कश्मीर, भारत के अनन्तनाग ज़िले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी पर एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान गयी। कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बैसरन घाटी में टूरिस्ट फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे। तभी गोलियां चलने लगी। फायरिंग वाली जगह से दूर टूरिस्ट्स पर कोई असर नही पड़ा। वे अपनी मस्ती में डूबे थे। थोड़ी देर में ही उन्हें भी समझ आ गया कि हमला हुआ है। जंगल की तरफ से आए आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्होंने धर्म पुछा और 10 से 15 मिनट में 26 लोगों को मार दिया। फिर वापस जंगल में गायब हो गए। उनका अब तक पता नही चला। मृतकों में एक मुस्लिम कश्मीरी भी शामिल हैं जो वहां घोड़ा चलते है, पर्यटकों की जान बचने के लिए वो अताक़ादियों से भीड़ गये जिसके बाद आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। बताया जा रहा है कि कुल 5 आतंकी थे। इनमें तीन लोकल और दो विदेशी हैं। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के छद्म संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर घाटी में हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

आखिरकार भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है 'ऑपरेशन सिंदूर'। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डॉयरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नही किया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था।

भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 25 घंटे बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (DGMO) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, आप सभी अब तक उस क्रूरता और नृशंस तरीके से परिचित हो चुके हैं, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। पहलगाम के भयावह दृश्यों और परिवारों के दर्द को देखने के बाद निहत्थे नागरिकों पर हाल ही में हुए कई अन्य आतंकवादी हमलों की याद भी आई। सेना जानती थी कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प को दिखाने और एक दमदार बयान देने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंक के अपराधियों और साजिश रचने वाले लोगों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी। भारत आतंक को नही सहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तीनों सेनाओं के अधिकारी जब प्रेस ब्रीफिंग करने पहुंचे तो ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति चलाई गई। इसके माध्यम से भी भारतीय सेना ने स्पष्ट संदेश दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल किया गया वह- शिव तांडव स्तोत्र का है। एयरमार्शल एके भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और मेजर जनरल एसएस शारदा ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर जानकारी दी।

नही बदला भारत का फैसला

भारत और पाकिस्तान ने पिछले ढ़ाई दशक में सबसे तीव्र लड़ाई देखी थी। चार दिनों तक बढ़ते संघर्ष में फाइटर जेट, मिसाइलें और विस्फोटकों से भरे ड्रोन शामिल थे। पाकिस्तान को अपनी हिमाकत के लिए मुंह की खानी पड़ी थी। भारत ने उसके हर हमले को रोक दिया था और उसे जवाबी हमले में बड़ी चोट पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा था। आखिरकार 10 मई के दिन पाकिस्तान को थक हारकर बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। उसकी सेना ने भारत की सेना को कॉल घुमाया और सीजफायर की बात की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल के अनुसार, "इस कॉल के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को पाकिस्तानी उच्चायोग से अनुरोध दोपहर 12.37 बजे मिला था। पाकिस्तानी पक्ष को तकनीकी कारणों से हॉटलाइन कनेक्ट करने में शुरुआती दिक्कतें आईं। फिर भारतीय डीजीएमओ की उपलब्धता के आधार पर बातचीत के लिए 3:35 बजे का समय तय किया गया।" उन्होंने बताया कि 10 तारीख की सुबह, भारत ने पाकिस्तान वायु सेना के प्रमुख ठिकानों पर बेहद प्रभावी हमला किया था। यही कारण है कि पाकिस्तान अब गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने को कहने लगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा कि "भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया था।" भारत ने पाकिस्तान की संघर्ष रोकने की यह अपील स्वीकार कर ली थी। भारत का प्राथमिक लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के ठिकानों को निशाना बनाने जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कदम के साथ कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीजफायर लागू हो गया। भारत ने कह दिया था कि भले बॉर्डर पर हमला न हो लेकिन ये 6 फैसले नही बदेलेंगे:

1. पहले की तरह ही सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा
2. अटारी का इंटीग्रेटेड बॉर्डर भी बंद रहेगा
3. पाकिस्तानियों के लिए हर वीजा सर्विस पर रोक बनी रहेगी
4. पाकिस्तान के साथ हर बिजनेस / ट्रेड पर रोक बनी रहेगी
5. पाकिस्तान के लिए भारत का एयरस्पेस बंद रहेगा
6. पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट्स पर बैन बना रहेगा

खैर वह पाकिस्तान ही क्या जो वादे निभाए और नियम-कानून से काम करे। उसने कुछ घंटे बीतते ही सीजफायर का उल्लंघन किया और भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। भारत के सशस्त्र बलों ने इन उल्लंघनों पर पर्याप्त और उचित जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने दोबारो सीजफायर तोड़ने की गलती नही की।

योगी का 'ब्रह्मास्त्र'

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिन्दूर के तहत भारत ने एक तरफ जहाँ पकिस्तान को धुल चटाया तो वहीँ लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के इनॉगरेशन की ख़बर ने उत्तर प्रदेश की मजबूत तस्वीर को भारत के सामने रखा। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के इनॉगरेशन में दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली जुड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ यूनिट में रहे। इस दौरान राजनाथ ने कहा, ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। 1 फरवरी, 2018 की बात है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 में देश में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी के लिए। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 6 शहर- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ को चुना गया। वित्त मंत्री की घोषणा के 7 साल 3 महीने बाद लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का इनॉगरेशन किया गया। खबर के अनुसार ये दो तारीखें यूपी के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी अहम हैं। हम डिफेंस सेक्टर के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। लखनऊ से लेकर चित्रकूट तक में एक्सप्रेस-वे के किनारे बने रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीनों का अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। यूपी सरकार के मुताबिक, जनवरी 2025 तक डिफेंस कॉरिडोर के लिए यूपी सरकार ने 169 कंपनियों के साथ करीब 28 हजार 4 सौ 75 करोड़ रुपए के समझौते (MOU) किए हैं। इनमें से 57 कंपनियों को जमीन अलॉट की जा चुकी हैं। 87 कंपनियों को जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। कुल 1649 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जा चुकी है। सभी यूनिट लग जाने के बाद करीब 46 हजार 667 लोगों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक, अगले चार वर्ष में सिर्फ यूपी से 25 हजार करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। मिसाइल, ड्रोन, गोला-बारूद और छोटे हथियारों की सप्लाई में सबसे बड़ा सप्लायर होगा।

मिसाइल यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य मौजूद रहे। सीएम योगी ने मिसाइल के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान सीएम योगी ने आतंकवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। अगर नही देखी, तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधी नही होने वाली और न ही प्यार की भाषा समझने वाली है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसी मानी जाएगी। याद रखना, जब तक हम आतंकवाद को पूरी तरह कुचल नही देंगे, तब तक समस्या का समाधान नही होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर न हो। पूरी दुनिया में युद्ध अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जिनके पास रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता नही है, वे अलग-थलग पड़ गए हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल ने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए।

300 करोड़ लागत से साढ़े 3 साल में बनी मिसाइल यूनिट

ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में है। यह यूनिट ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने 2021 में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्लांट का शिलान्यास किया था। सिर्फ साढ़े 3 साल में यह यूनिट बनकर तैयार हो गई। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस की सरकारी कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) का संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) है। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। यह भारत का पहला ऐसा रक्षा संयुक्त उद्यम है, जिसे किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर शुरू किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब एक ऐसा रूट होता है, जहां सेना की जरूरत का सामान बनाया जाता है। इसमें जवानों की वर्दी से लेकर बड़े-बड़े हथियार, ग्रेनेड, टैंक, आर्मी ट्रक, ऐम्बुलेंस, हेलमेट आदि शामिल हैं। भारत अब तक हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए बड़ी हद तक विदेशों पर निर्भर रहा है। इसे दूर करने के लिए देश में ही रक्षा उपकरणों को निर्माण किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा।

डिफेंस कॉरिडोर में कहां क्या बन रहा

- **लखनऊ:** ब्रह्मोस मिसाइल, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर
- **कानपुर:** हल्के एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, ड्रोन और स्नाइपर राइफल जैसे 41 तरह हथियार
- **झांसी:** गोला-बारूद, मिसाइल
- **आगरा:** रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट
- **अलीगढ़:** ड्रोन, एंट्री ड्रोन, माइंस-सेंसर, पिस्टल, रिवॉल्वर

ABT
अपना भारत टाइम्स

यूपी में "चिराग"

जाति जनगणना के एलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग बदलता हुआ नज़र आ रहा है, कभी जाति जनगणना से मुंह फेरने वाली भाजपा की केंद्र सरकार ने ही सामाजिक जरुरत बता कर जाति जनगणना का एलान कर दिया. अब बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इसका फायदा किसको मिलेगा? एक तरफ पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मजबूती स्थिति के लिए रामजी लाल सुमन का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं तो वहीँ बसपा बहुजन समाज के मतदाताओं से अपील कर रही है कि भाजपा और कांग्रेस पर भरोसा न करें. लेकिन इन सबके बिच असल भूमिका में एनडीए के सहयोगी दल नज़र आ रहे हैं यानि भाजपा के साथी. प्रदेश में सुभासपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी तो मैदान में है ही लेकिन इनके टूटते बनते जनाधार के बिच मोदी का हनुमान कहे जाने वाले केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पैर जमाना शुरु कर दिया है. बिहार में विपरीत परिस्थियों में लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने वाली लोकजनशक्ति पार्टी रामविलास, केंद्र में भाजपा की मजबूत साथी है.

उत्तर प्रदेश में लोजपा (र) के प्रदेश अध्यक्ष युवा सिद्धिनाथ मिश्रा "सिद्धांत" ने बताया कि "हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ कड़ी हो रही है, हम हर जिला स्तर और बूथ स्तर पर सदस्यता आभियान चला रहे हैं, हमने कई जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां की हैं, इसी क्रम में हमने पासी समाज से आने वाले प्रवीन कुमार को उन्नाव का जिलाध्यक्ष बनाया है, हम 2027 के विधान सभा चुनाव में भाजपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, हमारा लक्ष्य सबका साथ, हमारी जिम्मेदारी - सबकी हिस्सेदारी." अब बड़ा सवाल है कि जब भाजपा के साथ ऐसे दलों का गठबंधन है जिनका विभिन्न जातियों अच्छी पकड़ है और सपा का इतिहास दलितों के हित में नही रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन भारी?

कैसे लागू होगी जाति जनगणना?

केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक BJP इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी बोले- कहा था ना, मोदी जी को 'जाति जनगणना' करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाली मूल जनगणना में ही शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं, बताया जा रहा है कि देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सिंतबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा, इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं।।

जाति जनगणना और राजनीति

कांग्रेस समेत BJD, सपा, RJD, बसपा, NCP शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। TMC का रुख साफ नही है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। भाजपा पहले जाति जनगणना के पक्ष में नही थी। हालांकि, बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। 2024 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। सम्भावना है कि केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पर UP और बिहार में BJP का गैर यादव OBC वोट शेयर कम होने की वजह से ये फैसला लिया हो, इस फैसले से BJP को बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी।

जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट बनेगी

देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। 2011 की जनगणना में जाति-उपजाति का आंकड़ा 46.73 लाख मिला था। यह अविश्वसनीय माना गया था। आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें 4,147 जातियां बताई गई थीं। मंडल कमीशन ने 1980 में अनुमान लगाया था कि ओबीसी 52% हैं। अनुसूचित जाति में 28 राज्यों में 1109 जातियां हैं। अनुसूचित जनजाति में 705 जातियां हैं। सामान्य श्रेणी की जातियों की आबादी 30% और जातियों के बाहर मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग की आबादी 12.56% है। यह संख्या अनुमान और सर्वे आधारित हैं। जाति जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी, ताकि सुनियोजित डेटा इक्ट्ठा हो। जातियों पर राजनीतिक सहमति के लिए इसे सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के सुझावों-आपत्तियों के आधार पर सूची फाइनल होगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा जातीय जनगणना पर कांग्रेस खुद को जनता की हितैषी बताने में जुटी है, लेकिन वह यह भूल गई कि आरक्षण व सामाजिक न्याय को कमजोर करने का सबसे पुराना रिकॉर्ड उसी के नाम है।

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह भाजपा चुनाव में धांधली करती है। अधिकारी लगाकर वोट नही डालने दिया। उसी तरह जातीय जनगणना में भी धांधली कर सकती है। उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार को इसके प्रति सचेत रहना होगा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की कम्युनल राजनीति का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी, गरीबी पर सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए भाजपा जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रही है।

पूर्वांचल बना ख़ास

जाति जनगणना के बाद असली उठापटक पूर्वांचल के विधानसभा क्षेत्रों में होना तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से स्पष्ट जनाधार नही मिलता है। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की पांच सीटों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में भाजपा की सियासी व्यूह रचना नाकाम साबित हुई। लिहाजा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता मनोज सिन्हा तक को हार का सामना करना पड़ा। वहीँ 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 24 सीटों में 14 सीटें सपा ने जीती थी जबकि 10 सीटों पर भाजपा और इसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) को जीत मिली थी। वहीँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2022 में प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। इसके बावजूद पूर्वांचल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नही था। वर्ष 2022 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी पांच विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। इसी तरह से लालगंज (सु.) लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों पर भी भाजपा हारी। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में से एक पर भी भाजपा उम्मीदवार जीत दर्ज नही कर सका था। घोसी लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर भाजपा को जीत मिली। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में भाजपा दो पर ही जीत दर्ज कर पाई।

योगी के सहारे पूर्वांचल

राजनिति के जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी सरकारें आती हैं तो सबका एक विशेष क्षेत्र पर फोकस होता है। बसपा में लखनऊ और नोएडा पर फोकस था तो अखिलेश सरकार में इटावा क्षेत्र में फोकस था। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर से हैं और PM मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है तो ऐसे में केंद्र और राज्य का फोकस पूर्वांचल पर होना लाजमी है। जबकि बसपा या सपा को पूर्वांचल में बढ़िया सीट मिलने के बाद भी इनका पूर्वांचल पर फोकस नही रहा। योगी आदित्यनाथ चूंकि खुद पूर्वांचल से हैं और 2017 में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया है और 2022 में उन्हें सत्ता तो मिली लेकिन पूर्वांचल से निराशा हाथ लगी। दो साल बाद साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। ज़ाहिर है तब तक शायद सेंसस ना हो पाये, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अगले दो साल सभी जातियों के पास जाएगी और सीधा निशाना सपा-कांग्रेस पर साधेगी। पूर्वांचल की रस्साकसी को इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि पूर्वांचल मजबूत होने से जहां भाजपा मजबूत होगी। योगी खुद भी मजबूत हो जाएंगे। सभी जानते हैं कि पूर्वांचल के 30 से 35 विधानसभा सीटों पर योगी अपना असर रखते हैं। अब इस असर को बढाने की कवायद है।

2017 में भाजपा को मिला था जनसमर्थन

1991 के बाद साल दर साल भाजपा का प्रदर्शन कमजोर होता गया। 1991 के बाद 2017 में भाजपा को पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीट मिली थी। जोकि भाजपा का अब तक का रिकॉर्ड है।

जनपद	विधानसभा सीट	2017	2012	2007
आजमगढ़	10	1	0	0
जौनपुर	09	4	1	1
गाजीपुर	07	3	0	0
मऊ	04	3	0	0
बलिया	7 (2007 तक 8)	5	1	0
संतकबीरनगर	3 (2007 तक 4)	3	0	0
चंदौली	4	3	0	0
अंबेडकरनगर	5	2	0	0
प्रतापगढ़	7	2	0	1
प्रयागराज	12 (2007 तक 11)	8	0	1

यूपी में राजनैतिक दलों की ताक़त धर्म और जाति

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दलों की ताक़त धर्म और जाति है। वर्तमान में बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर मज़बूत है, तो वही पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ताक़त जातीय समीकरण है। इनके अलावा क्षेत्रीय दलों की एकमात्र ताक़त जाति है। इनमें ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा, डॉ संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिय पटेल की अपना दल (एस), जयंत चौधरी की आरएलडी, पल्लवी पटेल की अपना दल (करनेवाली) जैसे दलों ने सत्ता में हिस्सेदारी सिर्फ जातियों के बल पर पाई है। यूपी में राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों का दावा है कि मंडल आयोग की सिफ़ारिशें आंशिक तौर पर लागू हुई हैं। ऐसे में पिछड़ो की राजनीति करने वाले सुभासपा से लेकर निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियां एससी/एसटी के साथ साथ पिछड़ों को लोकसभा और विधानसभा में कोटा दिए जाने की मांग उठा सकते हैं।

गाज़ीपुर में कौन बचाएगा भाजपा की ज़मीन ?

जनपद गाजीपुर भाजपा के महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ भाजपा को अपने पैर ज़माने में काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन पूर्ण सफलता अब तक नही मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में बदलाव की लहर चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी अपने पैर देश की राजनीति में मजबूती से जमा रही थी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में भाजपा का सुखा ख़त्म हो रहा था और मनोज सिन्हा के रूप में भाजपा ने अपनी मजबूत वापसी की। मनोज सिन्हा को केन्द्रीय मंत्री बनाया गया, जिसके बाद गाजीपुर में कई योजनाओं के जरिये विकास कार्य करवाए गये। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता गाजीपुर में नही खुला था लेकिन 2017 में भाजपा को 7 में 3 सीटें हासिल हुईं। लेकिन ये जनसमर्थन ज्यादा दिन नही टिका और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, यही हाल 2022 विधानसभा चुनाव में रहा और भाजपा खाता नही खुला, स्थिति और बिगड़ी 2024 का लोकसभा चुनाव भी भाजपा यहाँ से हार गयी। मनोज सिन्हा के बाद गाजीपुर जनपद में भाजपा का कोई मजबूत चेहरा नही बचा, लेकिन यूपी सरकार के पूर्व मंत्री विजय मिश्र के भाजपा में आने से भाजपा का जनसमर्थन मजबूत होने की उम्मीद जगी। तो वहीँ पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नजदीकियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के अन्दर उर्जा भरने का काम किया है। ये दोनों नेता जनपद में मजबूत जनसमर्थन रखते हैं और आपने कार्यकाल में किये गये विकास कार्यों से आज भी इनकी पहचान है। जानकारों का मानना है कि भाजपा इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।

यूपी की "ऊर्जा"

वर्ष 2025 के मई का अंतिम सप्ताह उत्तर प्रदेश में उर्जा क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 30 मई 2025 को एक नया इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तापीय विद्युत परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं से प्रदेश में न सिर्फ 24.89% उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश की उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जो प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान देगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नही, बल्कि उत्पादक राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सौगात और योगी सरकार की सतत ऊर्जा नीति ने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है। आने वाले वर्षों में यह ऊर्जा विस्तार हर घर में रोशनी, हर खेत में बिजली और हर युवा को अवसर देने का आधार बनेगा। इन तापीय परियोजनाओं के शुभारंभ से प्रदेश को बड़े लाभ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर होगा। 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 15,916 मेगावाट थी। योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 24,868 मेगावॉट तक पहुंचा दिया है और इस वर्ष के अंत तक यह क्षमता 27,184 मेगावॉट हो जाएगी। सभी नई परियोजनाओं में सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे कम कोयले में ज्यादा बिजली बनती है। इससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है और पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है।

ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियां

- 1 करोड़ 78 लाख से अधिक विद्युत संयोजन निर्गत
- 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण
- 13 बड़े तापीय बिजली घरों पर काम शुरू
- 9,000 मेगावाट के संयंत्र पहले ही चालू
- जवाहरपुर तापीय परियोजना (2x660 मेगावाट)
- घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना (1x660 मेगावाट)
- पनकी तापीय विस्तार परियोजना (1x660 मेगावाट)
- ओबरा-सी तापीय परियोजना (2x660 मेगावाट)
- खुर्जा तापीय परियोजना (2x660 मेगावाट)

राजस्व में होगी वृद्धि

इन परियोजनाओं से प्रदेश के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नई परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का 75.11% हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 24.89% असम को भेजा जाएगा। इससे प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा और ऊर्जा वितरण में संतुलन बनेगा। बिजली आपूर्ति की मजबूती से कृषि कार्यों, घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। सिंचाई सस्ती होगी, फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा।

रोजगार सृजन

इन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही इन परियोजना क्षेत्रों में सड़क, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आधारभूत ढांचे का भी विकास हो रहा है। आगामी 10 वर्षों के लिए योगी सरकार ने 10,795 मेगावाट तापीय ऊर्जा और 28,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की व्यापक योजना बनाई है। इससे न केवल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय ऊर्जा

श्रमिकों के लिए योगी सरकार शुरू करेगी सुविधा केंद्र और श्रमिक सराय

मई 2025 का आखिरी सप्ताह श्रमिकों के लिए भी ख़ास रहा, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में योगी योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र और विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ श्रमिकों की दैनिक समस्याओं को हल करने जा रही है, बल्कि उन्हें गरिमा और सुविधा के साथ जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि प्रथम चरण में राज्य के 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को श्रमिकों के लिए एक वन-स्टॉप समाधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उन्हें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पंजीकरण सुविधा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, और आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। बीते दिनों श्रम विभाग ने सीएम योगी के समक्ष इन योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया। इन केंद्रों के माध्यम से योगी सरकार का लक्ष्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाई जाए, ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी लाभों से वंचित न रहे। प्रदेश में प्रवासी निर्माण श्रमिकों की संख्या बड़ी है जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। इनकी रातें अक्सर फुटपाथ या असुरक्षित स्थानों पर गुजरती हैं। ऐसे में योगी सरकार की विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल के रूप में राहत लेकर आ रही है। इन सरायों में स्वच्छ शौचालय, स्नानागृह, क्लॉक रूम और अस्थायी आवास की सुविधा होगी, जिससे श्रमिक न केवल सुरक्षित रह सकेंगे बल्कि अगली सुबह नए काम की तलाश में बेहतर ढंग से निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिक कल्याण को लेकर गंभीर हैं और कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि राज्य का निर्माण करने वाले श्रमिकों को सुविधाएं देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनकी इसी सोच का परिणाम है कि यूपी में पहली बार श्रमिकों के लिए इस तरह के स्थायी ढांचे की योजना बनाई जा रही है, जो श्रमिकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सके। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में इन योजनाओं का विस्तार हर नगर क्षेत्र और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों तक किया जाए, ताकि कोई भी श्रमिक सुविधाओं से वंचित न रहे। इन दोनों योजनाओं के जरिए योगी सरकार न केवल श्रमिकों के जीवन को आसान बना रही है, बल्कि सशक्तीकरण, सुरक्षा और सम्मान की उस राह पर भी उन्हें आगे बढ़ा रही है, जो अंततः राज्य के समग्र विकास को गति देगा। आने वाले वर्षों में जब ये योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरेगा।

यूपी के स्कूल

3300 करोड़ रुपये की परियोजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा को समाज और राष्ट्र की आधारशिला बताते कहा कि यह बच्चों के भविष्य को संवारने का सबसे मजबूत हथियार है। 26 मई 2025 को ख़बर आई कि लोकभवन सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने 3300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रदेश के 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों व अतिरिक्त डॉरमेट्री का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम योगी ने 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों एवं 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति छात्र-छात्रा ₹1,200 की धनराशि उनके अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। सीएम योगी ने 7,409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 5,258 विद्यालयों में आईसीटी लैब, शिक्षकों को 51,667 टैबलेट्स वितरण, 503 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में स्थापित एडुकेशनल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, कक्षा 3 से 12 के छात्र-छात्राओं के स्मार्ट असेसमेंट हेतु निपुण प्लस एप, समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में समर कैंप नवाचार का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था का बोलबाला था। छात्रों की कमी और ड्रॉपआउट दर अधिक थी। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प ने इस तस्वीर को बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय इस अभियान से जुड़ चुके हैं और शेष 2-3 प्रतिशत विद्यालय भी इस वर्ष कायाकल्प के दायरे में आ जाएंगे। इन स्कूलों में अब शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों में छात्रों की संख्या 800-1200 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा का एक नया मॉडल है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात हर हाल में बनाए रखा जाएगा। शिक्षकों की कमी नही होगी। हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक होंगे, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने बीएड और एमएड के छात्रों को निपुण आकलन कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया, ताकि उन्हें फील्ड अनुभव मिले और वे स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाओं से परिचित हो सकें। सीएम योगी ने कहा कि यह उनके लिए एक नया अनुभव होगा और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएगा। सीएम योगी ने समर कैंप को बच्चों के समग्र विकास का माध्यम बताते हुए इसमें खेल, संगीत, नृत्य, नाटक और योग जैसी गतिविधियों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए हर विद्यालय में अभी से प्रशिक्षण शुरू हो। आयुष मंत्रालय के योग प्रोटोकॉल को लागू करें और बच्चों को तनावमुक्त करने के लिए इनडोर गतिविधियों को बढ़ावा दें। उन्होंने नवंबर-दिसंबर में स्कूली खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को ब्लॉक, जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर आयोजित करने की योजना के बारे में बताया, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके।

मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय

मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 25-30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये विद्यालय प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, और मल्टीपर्पज हॉल के साथ ये स्कूल शिक्षा का एक नया मॉडल होंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा जो बच्चों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देगा।

छात्रों को 1200 रूपये

सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे, और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये प्रति छात्र प्रदान करने की योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह धनराशि सीधे बच्चों के खाते में जाती है। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि यह राशि बच्चों की जरूरतों पर ही खर्च हो। उन्होंने 'स्कूल चलो अभियान' को गति देने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक और प्रधानाचार्य घर-घर जाकर 5-14 वर्ष के बच्चों को स्कूल से जोड़ें। गांव में कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहे।

मुख्तार के बेटे अब्बास को सज़ा

मई 2025 के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हो गया है. सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी। आने-जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी. दरअसल, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों के 'देख लेंगे'। यह बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था। इसके बाद सब-इंसपेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल किया था। अब्बास अंसारी पर जो केस दर्ज किया गया, उसमें आपराधिक धमकी देने, चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। अब सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है।

CJI बोले- योगी देश के सबसे पावरफुल सीएम

मई 2025 के आखिरी दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई पहली बार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा, 'अभी-अभी मंत्री मेघवाल जी ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल हैं ही।' CJI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और वकील चेंबर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- इस देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब तक बार और बेंच साथ में काम नहीं करते, तब तक हम न्याय के रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। योगी ने कहा- महाकुंभ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही। अगर कोर्ट कुंभ के पहले अगर किसी काम में स्टे कर देता तो यह सफलतापूर्वक संपन्न न हो पाता। CJI ने कहा- आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जिसे हम रोल मॉडल बोल सकते हैं। मेरे नॉलेज में इतनी बड़ी इमारत वकीलों के लिए पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। यहां वादकारियों का भी ख्याल रखा गया। बगल के भूखंड में वादकारियों के लिए कुछ प्लानिंग है, जहां बच्चे लेकर आने वाली महिलाओं के लिए क्रैच भी बनेगा। यानी वर्किंग महिला के बच्चों के लिए देखरेख की व्यवस्था की जाएगी।

योगी ने कहा- याद कीजिए इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2017 में PM मोदी का आगमन हुआ था। उन्होंने कहा था- सुशासन की पहली शर्त है- रूल ऑफ लॉ। यानी कानून का शासन। इसमें बार और बेंच के साथ-साथ वादकारी का भी महत्व है। प्रयागराज धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। महाकुंभ में कौन सा व्यक्ति होगा, जिसने त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपनी विरासत के साथ जोड़ने में गौरव की अनुभूति न की हो। 6 साल पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मल्टीलेवल पार्किंग बनाई था। मगर, यह नहीं चली नहीं। मैंने कहा- चलेगी भी नहीं। सबसे पहले ऊपर के दो फ्लोर कॉमर्शियल कर दीजिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अब वहां कॉम्प्लेक्स फुल है। यहां पर मल्टीलेवल पार्किंग के साथ-साथ वकीलों को चेंबर दिए गए हैं। वकीलों के ये एसी चेंबर आप लोगों को भी ठंडा करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- ये इज ऑफ लिविंग की व्यवस्था हैं। पार्किंग को लेकर होने वाले विवाद अब कम हो जाएगा। सबसे जल्दी काम करना सीखना हो तो सीएम योगी से सीख सकते हैं। महाकुंभ में शानदार कोआर्डिनेशन के लिए सीएम योगी की प्रशंसा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- इलाहाबाद बार एसोसिएशन बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझ पाता है कि यहां काम कैसे होता है। इस बिल्डिंग का पूरा सदुपयोग कीजिएगा।

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई

जन्म- 24 नवंबर 1960

स्थान- अमरावती (महाराष्ट्र)

CJI गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डिमॉनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना आदि है।